# बंद कर दिए दुकान, नहीं गए मीट मार्केट

## खुले में मांस बिक्री को लेकर एक बार फिर आज कलेक्टर के आदेश के पालन में मीट-मटन दुकानदारों को मीट मार्केट शिफ्ट कराने गए नपा अमले को बंद मिली दुकानें

नवभारत मुहिम नवभारत

**सीधी 1 जून। मीट मार्केट में जाने की बजाय दुकान बंद कर दिये। खुले में मांस बिक्री को लेकर एक बार फिर आज कलेक्टर के आदेश के पालन में मीट-मटन दुकानदारों को मीट मार्केट शिफ्ट कराने गए नपा अमले को दुकानें बंद मिली।**

गौरतलब है कि शहर में खुले में चिकन बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर 1 जून 2026 से मीट मार्केट में ही कारोबार करने का अल्टीमेटम कलेक्टर द्वारा निरीक्षण के बाद दिया गया था। कलेक्टर ने खुले में चिकन बिक्री की स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात खुले में चिकन बिक्री पर प्रशासन का सख्त रुख सामने रखा। शहर में स्वच्छता और जनस्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। जिसकी शहरवासी प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल मीट कारोबारियों की मनमानी से शहरवासी लम्बे अर्से से त्रस्त थे। मीट कारोबार से समूचे इलाके में भारी प्रदूषण एवं बदबू की स्थिति हर समय निर्मित रहती थी। अब शहरवासियों की अपेक्षा है कि बाजार क्षेत्र में किसी भी तरह मीट का कारोबार खुले में ना हो, यह कारोबार मीट मार्केट से ही शहर में संचालित हो।

### छूट मिली तो निगरानी के अभाव में हमेशा की तरह सड़क में होगी बिक्री

प्रशासन द्वारा जिस सख्ती के साथ आज 1 जून से बाजार क्षेत्र एवं खुले में मीट बिक्री के कारोबार को बंद कराया गया है, वही सख्ती आगे भी बरकरार रखने की जरूरत है। यदि निगरानी में किसी भी तरह की शिथिलता दी गई तो पूर्व की तरह फिर से कारोबारी बाजार क्षेत्र से ही मीट का कारोबार संचालित करना शुरू कर देंगे। कारोबारियों की मनमानी यह थी कि उनके द्वारा शहर के मुख्य मार्गों के किनारे ठेलों एवं गोमतियों में मीट का कारोबार सब्जी की तरह संचालित किया जा रहा था।

### व्यवसाय बदल देंगें, नहीं जाएंगे मीट मार्केट

लालता चौक में प्रतिबंधित के बावजूद मीट मटन की खुलेआम खुले में बिक्री करने वाले लालता चौक के मीट-मटन दुकानदारों के बीच हो रही चर्चा को यदि सही माना जाये तो उनका स्पष्ट कहना है कि मीट मार्केट में मीट-मटन को स्टोर करने सहित पर्याप्त व्यवस्था एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नही है। इसलिए हम यहीं प्रशासन की शर्तों के साथ बंद शीशे के अंदर अपने व्यवसाय करेंगे। शर्तों का उलंघन करने वालों पर प्रशासन जो भी कार्यवाही करेगा हमें मंजूर है। लेकिन हम लोग मीट मार्केट नही जायेंगे, फिर चाहे हमें अपना व्यवसाय ही क्यों ना बदलना पड़े।

### बंद दुकानों से फिर शुरु होगा चोरी छिपे मीट बिक्री का खेल

शहर के बाजार क्षेत्र में मीट के कारोबार को बंद कराने और मीट मार्केट से कारोबार संचालित करने की पहल पूर्व में भी प्रशासन द्वारा की गई थी। उस दौरान भी कारोबारियों द्वारा दिखावे के लिये अपनी दुकानों का शटर गिरा दिया गया था और आसपास से मीट की बिक्री की जाती थी। बाद में प्रशासनिक शिथिलता होने पर उनके द्वारा फिर से अपनी दुकान से ही कारोबार शुरू कर दिया जाता था। इस बार भी बंद दुकानों की आड़ में चोरी छिपे मीट बिक्री का खेल शुरू होगा, जिस पर प्रशासन को सख्त नजर रखने की जरूरत है।

### बंद शीशे के अंदर मीट बिक्री करने के किए जाएंगे खोखले दावे

मीट कारोबारियों द्वारा सालों से खोखले दावे किये जाते रहे हैं कि दुकान के बाहर शीशा लगाकर अंदर से मीट बिक्री की जावेगी। यह दावे हमेशा हकीकत से दूर रहे हैं। बंद शीशे के अंदर से मीट बिक्री का खोखला दावा करने के बाद कारोबारी खुले में अपना पूरा कारोबार संचालित कर रहे थे। शहरवासियों की मंशा के अनुसार नगरपालिका द्वारा लाखों की लागत से सर्व सुविधायुक्त मीट मार्केट का निर्माण कराया गया है। नियमानुसार मीट मार्केट से ही मीट का पूरा कारोबार संचालित होना चाहिये।

### इनका कहना है

बाजार क्षेत्र में संचालित सभी मीट दुकानें आज 1 जून से नहीं खुलेंगी इसकी पूर्व सूचना जारी की गई थी। नगर पालिका की टीम को निरीक्षण के दौरान लालता चौक क्षेत्र में संचालित मीट दुकानें आज बंद मिली हैं। यह अवश्य है कि मीट मार्केट में दुकानों का विस्थापन नहीं किया गया है। किन्तु अब बाजार क्षेत्र में कोई भी मीट दुकान संचालित नहीं होगी। इसके लिये सतत निरीक्षण चलेगा।

**प्रिया पाठक, डिप्टी कलेक्टर सह सीएमओ नपा सीधी**

# किसानों की सहमति के बिना खेतों में टॉवर निर्माण तत्काल रोका जाए : अजय

## पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से की हस्तक्षेप की मांग

- किसानों को अडानी कम्पनी चार गुना मुआवजा दे

**नवभारत न्यूज**

**सीधी 1 जून। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सीधी जिले के चुरहट क्षेत्र में पावर ट्रांसमिशन परियोजना के लिए किसानों की सहमति के बिना उनके खेतों में जबरन टावर बनाये जाने को पूरी तरह गैर-कानूनी, दमनकारी और किसानों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है।**

अजय सिंह ने कहा कि अडानी की कम्पनी के लोग खेतों में जबरन घुसकर किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ऊपरी पहुंच बताकर उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, विरोध करने पर किसानों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भले ही कम्पनी की पहुंच ऊपर तक हो लेकिन इस कृत्य को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी इस संबंध में बात की है और कहा है कि जब तक किसानों की सहमति और मुआवजे का निपटारा नहीं हो जाता तब तक मुख्यमंत्री प्रकरण में हस्तक्षेप कर महान पावर ट्रांसमिशन परियोजना के लिए टावर लगाने का काम तुरंत रोकें। श्री सिंह ने कहा कि किसान सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर उन्हें वर्तमान बाजार मूल्य से चार गुना ज्यादा मुआवजा मांग रहे हैं, उनकी यह मांग नियमानुसार है। फिर शासन-प्रशासन उनके साथ कम्पनी के दबाव में मनमानी और तानाशाही क्यों कर रहा है? उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर लगाम लगाने की मांग की है।

### किसानों के हक पर डाला गया डांका, होगा जन आंदोलन

पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके हितों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगी। अगर किसानों के हक पर डाका डाला गया, तो पूरे क्षेत्र में चक्का जाम और जन-आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

# पड़रा पटवारी के खिलाफ लामबंद हुई जनता, पटवारी को हटाने की उठी मांग

**नवभारत न्यूज**

**सीधी 1 जून। जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम पंचायत पड़रा हल्का पटवारी के खिलाफ ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। पटवारी के कारनामों से लोगों में नाराजगी है। जिनमें अधिकतर लोग आज कलेक्टर से मिलने भी आए थे।**

मालूम हो कि पटवारी के कारनामे एवं भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को लेकर शिकायत भी काफी हो चुकी है। ऐसे पटवारी को पड़रा सहित गोपदबनास तहसील से हटाने की मांग की गई है। इस संबंध में लिखित शिकायत देकर पड़रा निवासी चंद्रभान पाण्डेय ने बताया कि हल्का पटवारी पड़रा दीपक शुक्ला द्वारा लगातार अनियमितताएं की जा रही है। इस मामले में यह भी जानकारी दी गइ कि वह हल्के में आना उचित नहीं समझते बल्कि घर बैठे गिर्दावली का काम मनमानी तरीके से करते आ रहे हैं। जो किसान उनके यहां जाकर चढ़ोत्तरी करते हैं उनकी तो बनती है लेकिन जो नहीं करते उनकी भूमि को भी रिक्त भूमि दिखाकर पटवारी द्वारा नियम विरुद्ध काम किया जा रहा है। इसकी शिकायत 22 मई को कलेक्टर के यहां चंद्रभान पाण्डेय द्वारा की जा चुकी है।

पड़रा निवासी संतोष पाण्डेय ने बताया कि उन्होंने एक जमीन बाईपास के पास खरीदे थे। रास्ते के लिए पटवारी द्वारा पांच लाख रुपए की मांग की गई थी। न देने के कारण पटवारी दीपक शुक्ला द्वारा नामांतरण नहीं कराया गया। मामले की शिकायत वरिष्ट अधिकारियों तक की जा चुकी है।

इसके साथ ही यह भी पता चला है कि हल्का पटवारी द्वारा ग्रामीण जनों से फसल नुकसानी एवं अन्य मामलों में भारी-भरकम रकम की मांग करते हैं न देने पर उन्हें परेशान कर अपने हिसाब से काम किया जाता है। वहीं सीमांकन, नक्शा सुधार सहित अन्य मामलों में पटवारी की हठधर्मिता से ग्रामवासी काफी परेशान हैं। ऐसे पटवारी को हटाने के लिए कलेक्टर से लोगों ने आवेदन दिए हैं।

# परियोजना प्रशासक श्रीनिवास द्विवेदी सेवानिवृत्त

**सीधी 1 जून।** जनजातीय कार्य विभाग सीधी के परियोजना प्रशासक श्रीवानिवास द्विवेदी 31 मई को 36 वर्ष 4 माह के शासकीय सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। श्री द्विवेदी जनजातीय कार्य विभाग में मंडल संयोजक, प्रभारी सहायक आयुक्त, जनपद सीईओ के पद का निर्वहन भी सफलता पूर्वक किए। इनका स्वभाव ऐसा था कि सेवाकाल के दौरान सभी को उचित स्थान और सम्मान दिया जाता था। नेता, अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी सभी के बीच अपने स्वभाव को लेकर काफी लोकप्रिय रहे।

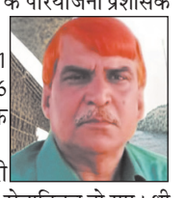

# कलेक्टर ने समय-सीमा बैठक में दिए कड़े निर्देश

**नवभारत न्यूज**

**सीधी 1 जून। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर विकास मिश्रा ने विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे तथा आमजन की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए।**

बैठक के दौरान कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर स्वयं हितग्राहियों से फोन पर चर्चा कर निराकरण की स्थिति की जानकारी ली तथा लंबित प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों एवं अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के अस्पतालों का सप्ताह में कम से कम दो बार निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध रहें तथा मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आबकारी विभाग को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित समय के बाद खुली मिलने वाली शराब दुकानों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी उपखंड स्तरीय अधिकारियों को अपने मुख्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहने तथा क्षेत्र के भीतर ही निवास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गौशालाओं, विद्यालयों, अस्पतालों, आंगनवाड़ियों एवं शासकीय पेयजल स्त्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने तथा दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नदियों, नालों एवं तालाबों के आसपास किए गए अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाया जाए। जल स्त्रोतों के आसपास अवैध निर्माण एवं पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी कॉलेज प्राचार्यों को विद्यार्थियों की उपस्थिति और आवागमन का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कॉलेज में ऐसा रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें विद्यार्थियों के प्रवेश एवं प्रस्थान का समय दर्ज हो। साथ ही स्कूलों के आसपास डॉग फ्री जोन विकसित करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू, पान मसाला एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने बताया कि खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए ई-विकास पोर्टल पर उर्वरक टोकन बुकिंग सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर ने कृषि अधिकारियों को खाद एवं बीज विक्रेताओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि नकली खाद-बीज बेचने वाले विक्रेताओं एवं फर्मों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई की जाए। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, एसडीएम बी.पी. पाण्डेय, सभी अनुविभागीय अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

# जनगणना-2027 के उत्कृष्ट कार्य पर शिक्षकों का सम्मान, प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र

**नवभारत न्यूज**

**सीधी 1 जून। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन, समर्पण एवं दायित्वों के सफल निर्वहन के लिए जिला प्रशासन सीधी द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जनगणना कार्य को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों को स्टार ऑफ द मंथ, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की गई।**

विशेष प्रशस्ति पत्र से सुशील कुमार खटीक उ.मा. शिक्षक, शाउमावि जूरी कुसमी को सम्मानित किया गया। जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन हेतु उन्हें कुसमी चार्ज अंतर्गत मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप कुसमी विकासखंड जिले में सर्वप्रथम शत-प्रतिशत मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य पूर्ण करने में सफल रहा। उनके दायित्वबोध, अनुशासन, कार्य कुशलता एवं समर्पण की जिला प्रशासन ने विशेष सराहना की। इसी क्रम में राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, प्राथ. शिक्षक शा.प्रा.शाला तेलियान टोला पांड मझौली, सुखनन्दन प्रजापति माध्य. शिक्षक, शा.मा.विद्यालय मुर्दाडीह सिहावल, सुरेन्द्र कुमार गुरदवान मा.शिक्षक शाउमावि फुलवा कुसमी तथा रावेन्द्र पाण्डेय उ.मा.शिक्षक शाउमावि अमरवाह गोपदबनास को जनगणना 2027 के दौरान सौंपे गए दायित्वों का उत्कृष्ट, निष्ठापूर्ण एवं समयबद्ध निर्वहन करने तथा प्रथम चरण के मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिला प्रशासन ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए निरंतर उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की।

# युवा कांग्रेस की आज निकलेगी चिमनी यात्रा

**नवभारत न्यूज**

**सीधी 1 जून। अघोषित बिजली कटौती, भारी-भरकम बिजली बिलों, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों एवं रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने मध्यम एवं गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।**

आम जनता लगातार इन समस्याओं से जूझ रही है किन्तु सरकार समाधान देने में विफल साबित हो रही है। इन्हीं जनसमस्याओं के विरोध में म.प्र. युवा कांग्रेस द्वारा चिमनी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। म.प्र. युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने बताया कि 2 जून को शाम 5 बजे गांधी चौक से अधीक्षण अभियंता कार्यालय जमोड़ी तक चिमनी यात्रा का आयोजन किया जायेगा। जिले के समस्त नागरिकों, युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कांग्रेसजनों से आग्रह किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर जनता की समस्याओं के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें तथा चिमनी यात्रा को सफल बनाएं।

# जिस उम्र में छात्र के हाथ में किताब हो, छात्र विश्वविद्यालय मांग को है मजबूर : कमलेश्वर

**नवभारत न्यूज**

**सीधी 1 जून। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सीधी के छात्र विश्वविद्यालय मांग रहे हैं न नौकरी मांग रहे हैं न कोई विशेष सुविधा।**

सिर्फइतना कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए 150 किमी. दूर भटकना न पड़े लेकिन भाजपा सरकार के लिए यह मांग भी शायद बहुत बड़ी है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और सपने होने चाहिए, उस उम्र में उन्हें सड़कों पर उतरकर विश्वविद्यालय मांगना पड़ रहा है जो सरकार एक जिले को विश्वविद्यालय तक नहीं दे सकती, वह युवाओं के भविष्य की बात किस मुंह से करती है? सीधी के विद्यार्थियों की यह लड़ाई सिर्फ एक विश्वविद्यालय की नहीं बल्कि शिक्षा के अधिकार और समान अवसर की लड़ाई है। ज्ञात हो कि सीधी जिले में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु पिछले कई साल से छात्र-छात्राओं की मांग चली आ रही है। इसी सप्ताह के शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं का छात्र संगठन सीधी मांगे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर सीधी को ज्ञापन सौंपा गया।

# बिजली की आंख मिचौली

**सीधी 1 जून।** जिला मुख्यालय में ही विद्युत आपूर्ति व्यवस्था गर्मी में लोड बढ़ने के साथ लड़खड़ाई हुई है। यह अवश्य है कि फाल्ट के नाम पर अलग-अलग क्षेत्रों में कब बिजली गुल हो जाय निश्चित नहीं रहता। देर रात में बिजली की गुल होते ही लोगों की नींद खुल जाती है। यह अवश्य है कि शहरी क्षेत्र होने के कारण विद्युत आपूर्ति बहाल हो जाती है।

# राजस्व न्यायालयों का विस्तार सुशासन की अवधारणा को मजबूत करने वाला कदम : डॉ .राजेश

## पटपरा को मिली प्रशासनिक सौगात, सांसद ने किया नायब तहसीलदार न्यायालय का शुभारंभ

**नवभारत न्यूज**

**सीधी 1 जून। क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को राजस्व एवं प्रशासनिक सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध कराने की दिशा में सोमवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई। उप तहसील (टप्पा) पटपरा में नायब तहसीलदार न्यायालय का शुभारंभ सांसद डॉ.राजेश मिश्रा द्वारा विधिवत किया गया।**

न्यायालय के प्रारंभ होने से अब क्षेत्रवासियों को नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भू-अभिलेख सुधार तथा अन्य राजस्व मामलों के लिए दूरस्थ तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि स्थानीय स्तर पर ही उनके प्रकरणों का निराकरण संभव हो सकेगा। शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सांसद डॉ.राजेश मिश्रा ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक सरल, सुलभ और समयबद्ध रूप से पहुंचें। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व न्यायालयों का विस्तार सुशासन की अवधारणा को मजबूत करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन लोगों के करीब पहुंचता है तो समस्याओं का समाधान भी तेजी से होता है और जनता का विश्वास भी बढ़ता है। सांसद डॉ.मिश्रा ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा स्थानीय स्तर पर राजस्व न्यायालय की मांग की जा रही थी। नायब तहसीलदार न्यायालय के प्रारंभ होने से न केवल आमजन का समय और धन बचेगा, बल्कि राजस्व मामलों के निराकरण में भी गति आएगी। इससे ग्रामीणों को त्वरित राहत मिलने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी।

कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार न्यायालय के शुभारंभ का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के विकास और जनसुविधाओं के विस्तार की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। वक्ताओं ने कहा कि इससे विशेष रूप से ग्रामीण, किसान और दूरस्थ गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा तथा राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक भागदौड़ कम होगी।

### आमजन को सुविधाएं उपलब्ध कराने प्रशासन प्रतिबद्ध : आनंद

उपखंड अधिकारी चुरहट विकास आनंद ने कहा कि पटपरा क्षेत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। न्यायालय के संचालन से स्थानीय स्तर पर राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण संभव होगा तथा नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है।

### कार्यक्रम में इनकी रही उपस्थिति

कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, के .के .तिवारी, जिला पंचायत सदस्य मनोज सिंह, तहसीलदार साक्षी गौतम सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।